KGG-DS/2B/2.00

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before I take up the formal Business, I would like to inform the House that at 5.30 p.m., we will take up the statement to be made by Shrimati Sushma Swaraj so that those who want to seek clarifications may do so after the statement. …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, during Question Hour today, the Minister concerned was not present. The Cabinet Minister was not present. What do you propose to do about that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That issue you can't raise here. You should have raised it at that point of time.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I had raised it. This is a gross insult to Parliament. The Minister concerned was not present, no Cabinet Minister was present. Is this the shape of things to come?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. The Cabinet Minister is here. All Ministers are here. …(Interruptions)… The issue relating to Question Hour should be raised at that point of time and not now. …(Interruptions)…

SHRI RAJEEV SHUKLA: The other day, the Home Minister had made a *suo motu* statement and it was decided that clarifications would be sought later.

A time has to be fixed for that, but nothing has been done as yet. Now, the External Affairs Minister would be making a statement and clarification on her statement would be sought today. How about the clarifications on the Home Minister's statement?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, we have agreed to that. Mr. Naqvi, please find out the convenience of the Home Minister and inform us so that we can have it. There is no problem; we will have it.

THE MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 2016

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016. Lok Sabha passed the same Bill which we had passed. There is only a technical Amendment. Therefore, it has been agreed to pass it without discussion. Now, the Minister may move.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I move:

> That the following amendments made by Lok Sabha in the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016, be taken into consideration, namely:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, ***for*** the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be ***substituted***.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, ***for*** the figure "2016", the figure "2017" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI BANDARU DATTAREYA: Sir, I move:

That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

(Followed by KLS/2C)

KLS/MCM/2C-2.05

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Budget discussion is unfinished, it is pending and we have also a Bill. Should we take up the discussion or the Bill? … (Interruptions)…

SOME HON. MEMBERS: Discussion. …(Interruptions)…

श्री नरेश अग्रवाल : महोदय, सुबह तय हो गया था कि कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा।.....(व्यवधान).... आज कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा। अभी बजट डिस्कशन के बहुत घंटे बाकी हैं।....(व्यवधान)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, it is an important Bill.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह गलत है। जो तय हो गया है....(व्यवधान)....

SHRI JAIRAM RAMESH: They are repeatedly bringing in other Business during Budget discussion. ...(Interruptions)... It is not a good precedent. ...(Interruptions).. Either the Budget discussion continues, Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is listed in the Business. I only asked the views of the House. ...(Interruptions)... That is why I am saying. It is listed in the Business. I was only asking the views of the House. ...(Interruptions)... In the morning also it was said. ...(Interruptions).. Naddaji, in the morning, consensus was that we will continue the discussion.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Then we can take it up tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, we can take it up tomorrow. ...(Interruptions)... We will continue the discussion on Budget. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, in the List of Business for the day, the order as such, perhaps, is not correct because this is unfinished discussion. So, the discussion must continue first.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are doing that.

SHRI ANAND SHARMA: What I am pointing out is that it should have been listed in that order because the House is continuing the discussion on Budget.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The problem is, I tell you, when Government considers that a Bill is important, they will try to push it. …(Interruptions)… They will try to push it. …(Interruptions)… Sharmaji, you were also in the Government. The Government always tries to push the Bill. That is what they are doing. …(Interruptions)…

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : दो बजे से डेढ़-दो घंटे तक लेजिस्लेटिव कार्य करेंगे। फिर उसके बाद.....(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government has finally to go by the will of the House. …(Interruptions)… So, there is no problem. …(Interruptions)… We will take up the discussion. …(Interruptions).. I agree with you. We will take up the discussion. …(Interruptions)… There is no problem. But the Government can always show its intention by trying to push a Bill. So, if possible, they will do that. …(Interruptions)… There is nothing unfair in that.

The Government will always try for that. It is for the vigilant House to stall, if you think such actions are against it. It is for the House to do it. You should be vigilant. Okay, we will now take up the Budget discussion.

(Followed by 2D/SSS)

SC-SSS/2.10/2D

THE UNION BUDGET, 2017-18 -- CONTD.

श्री शंकरभाई एन.वेगड़ (गुजरात) : डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तहेदिल से इस बजट का स्वागत करता हूं और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं।

सर, पिछले साल हर गांव को, हर घर को अच्छी तरह से बिजली मिले, इसके लिए आयोजन किया गया था। इस साल "पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के अंतर्गत 4,814 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायी है। सरकार ने 12,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का आयोजन किया है और सन् 2019 तक हिन्दुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाई जाए, ऐसा हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने आयोजन किया है, जो एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से "उजाला योजना" के अंतर्गत बिजली की बचत हो और सस्ते दाम पर बिजली के बल्ब्स, पंखे और ट्यूबलाइट्स मिलें, इसके लिए भी इस बजट में आयोजन किया गया है। हर गांव को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए भी इस साल 6,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया

गया है। हर गांव को अच्छा रास्ता मिले, अच्छी सड़कें मिलें, ताकि गांव वाले भी शहर में अपना business करने के लिए आ सकें, उनको गांव से शहर आने-जाने की अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" है। अब तक पिछली सरकार ने बीमा योजनाएं लागू की थीं, लेकिन इस योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसान जब बीज बोता है और अगर उसका बीज फेल हो जाता है तो इस बीमा योजना में प्रावधान होने के कारण उसको उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। पहले तहसील गिना जाता था, इस फसल बीमा योजना में अब गांव आते हैं और गांव में भी मान लीजिए एक साइड बारिश ज्यादा होती है और दूसरी साइड कम बारिश होती है और बहुत अधिक बारिश या सूखे के कारण 10-15 किसानों को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि उन 10-15 किसानों को भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। हर किसान को फसल के ऊपर अच्छी तरह से ऋण मिले, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अंतर्गत हर खेत को कृषि के लिए पानी मिले, इसका प्रबंध किया गया है - खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में।

इसी तरह से जब हम हर साल bore well से सिंचाई करते हैं तो जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। हम अगर ज़मीन से पानी निकालते रहेंगे तो कब तक चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि भूतल में पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" है कि बारिश का पानी जमीन में कैसे उतरे, इसके लिए भी इस बजट में आवंटन किया गया है। "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के

तहत 7,347 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हर खेत में soil की क्वॉलिटी क्या है - मनुष्य के शरीर की तो जांच होती है कि उसके शरीर में क्या कमियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, उसके खेत में क्या कमी है, आज तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह सरकार "Soil Health Card" की योजना लेकर आयी, जिसके अंतर्गत हर खेत की जांच की जाएगी कि खेत में क्या कमी है, किस तत्व की कमी है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा खाद मिले या अगर और किसी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त उसके खेत में क्या बोया जाए, ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। इस प्रकार 'Soil Health Card' की योजना लाकर इस सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है।

इसके अतिरिक्त मैं organic खेती की बात करना चाहता हूं। इस बजट में organic खेती के लिए कुछ रकम दी गयी है। सर, organic खेती करते समय खेत में जो बीज बोया जाता है, वह organic होता है। Organic खेती करते समय खेत में किसी तरह की रासायनिक खाद या fertilizer का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमारे हिन्दुस्तान के हर गांव को organic खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि organic खेती के लिए इस सरकार ने जो प्रावधान किया है, वह बहुत सराहनीय है।

(2ई-जीएस पर जारी)

GS-NBR/2E/2.15

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (क्रमागत): ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद भी चाहिए। उस ऑर्गेनिक खाद के लिए हमारे यहां गाय, भैंस, बैल होने चाहिए। इस सदन

में शर्म के मारे मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं कि गाय को काटने की बात करने वाले सदस्य भी इस सदन में मौजूद हैं। अरे, गाय नहीं बचेगी, तो हिन्दुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। गाय बचेगी, तो हिन्दुस्तान बचेगा। गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में इतनी ताकत है कि इस आधुनिक युग में जो कैंसर होता है, इसको मिटाने की कोई दवा सुझाई नहीं गई है, लेकिन गाय के गोबर और गौमूत्र में इतनी ताकत है कि यदि सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए, तो 100 परसेंट कैंसर मिट जाता है। जिसके आंगन में गाय बंधी रहती है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि रोग के जो जंतु अगल-बगल में होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। गाय के कारण उस परिवार में कोई आदमी बीमार नहीं होता है। यह इसका लाभ है, इसलिए मैं अपनी ओर से सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को गाय को बचाना पड़ेगा।

स्वस्थ भारत बने, स्वस्थता में प्रभु का वास है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, वेदों में भी कहा गया है। गांधी जी भी कहते थे कि स्वस्थता में प्रभु का वास है। इसलिए स्वस्थता के लिए 16,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा जन-धन योजना है। आज करीबन 23 करोड़ लोगों के जन-धन योजना में अकाउंट खुल गए हैं। इसके कारण सामान्य आदमी को, चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। जो गैस सब्सिडी मिलती है, उसका लाभ सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में चला जाता है। किसी के हाथ में पैसा नहीं जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक समय ऐसा था जब हमारे पंथ प्रधान भी कह चुके थे कि हम दिल्ली से एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं, लेकिन गरीब के पास पहुंचते-पहुंचते सिर्फ 15 पैसा रह जाता है और 85 पैसा

बीच में खाया जाता था, वह भ्रष्टाचार में चला जाता था। जन-धन योजना के कारण अब गरीब का पैसा सीधे उसके अकाउंट में चला जाता है और उसके बिना कोई बैंक से पैसा निकाल भी नहीं सकता है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे पंथ प्रधान और वित्त मंत्री जी ने किया है।

सर, कौशल विकास योजना और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हमारे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इस बजट में युवाओं को काफी तरजीह दी गई और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का संकल्प कार्यक्रम में पेश किया है। इसके तहत देश भर में साढ़े तीन करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष युवा और खेल मंत्रालय के बजट में कुल 335.11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत कॉरपस फंड को 1.22 लाख करोड़ रुपये से दोगुना 2.44 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के जरिए लाभ होने की बात कही जा रही है।

आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 में शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए युवाओं में ऊर्जा भरने को 10 क्षेत्रों में से एक बताया है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देश भर में 600 से अधिक जिलों तक पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा देश भर में 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर उन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रमों की भी पेशकश की जाएगी। जेटली जी ने कहा है कि इससे देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी, जो

देश के बाहर नौकरी के अवसर चाहते हैं। इसके अलावा 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्राइव योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और उद्योग संकुल दृष्टिकोण से प्रशिक्षु कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा।

मैं अब आवास योजना की बात करना चाहता हूं।

(HMS/2F पर जारी)

PK-HMS/2.20/2F

श्री शंकरभाई एन0 वेगड़ (क्रमागत) : महोदय, आवास योजना के लिए 29,033 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस के तहत अगले पांच वर्ष में देश के हर नागरिक के पास अपना घर होगा। वित्त मंत्री ने आम बजट में वर्ष 2022 तक देश के हर नागरिक को घर देने का वायदा किया है। इस के लिए आम बजट में सस्ती आवास योजना चलाने वाली कंपनियों के लिए मुनाफे से जुड़ी छूट को आकर्षक बनाया गया है। साथ ही अब तक 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल चार मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी, जब कि मेट्रो के बाहरी क्षेत्रों सहित देश के शेष सभी भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा लागू होगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण की अवधि को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपए के होम लोन का पुनर्वित्त करेगा।

महोदय, मैं "मनरेगा" के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। "मनरेगा" में पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ है ..(व्यवधान).. अब तक क्या चल रहा था, यह पूरे देश को मालूम है। इस का नतीजा आपने यू0पी0, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर देख लिया है। "मनरेगा" में केन्द्र सरकार ने सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए एक बार फिर "मनरेगा" पर भरोसा जताया है। विपक्ष में रहते हुए भा0ज0पा0 ने इस योजना की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन 2017-18 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कानून के तहत अब तक के सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल इस के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि पिछले साल के संशोधित बजट अनुमान में यह राशि 47,499 करोड़ रुपए हो गयी थी। "मनरेगा" के तहत सौ दिन के रोजगार के अलावा आधारभूत ढांचे के निर्माण पर फोकस किया जाएगा, पांच लाख तालाब बनेंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े पांच लाख तालाबों का काम शुरू किया जाएगा। यह पिछले साल पांच लाख तालाब और दस लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों के लक्ष्य के अलावा है। सरकार ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी 48 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गयी है।

महोदय, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार ने एक बार फिर अपना फोकस जाहिर किया है। मिशन के तहत पिछले वर्ष की तुलना में करीब पांच हजार करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ा है। बीते साल मिशन में 11,300 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यह राशि बढ़कर 16,248 करोड़ रुपए हो गयी है।

महोदय, महिला और बाल सशक्तीकरण के लिए भी इस बजट में ज्यादा-से-ज्यादा रकम आवंटित की गयी है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल

विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए बजट में गांव के स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में महिला और बाल कल्याण के लिए आवंटन 1,56,528 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,84,632 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ गांव के स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता प्रदान करेंगे। श्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत 6 हजार रुपए सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

महोदय, एक भारत स्वस्थ भारत, एक भारत स्वच्छ भारत के सूत्र को सार्थक बनाने के लिए इस बजट में बहुत सारी योजनाओं में बहुत बड़ी रकम का आवंटन किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का तहेदिल से स्वागत करता हूं और सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Mr. Vegad. Now, Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, माननीय नेता सदन कुछ अस्वस्थ हैं और आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। हमारी कामना है कि वे जल्दी से स्वस्थ हों।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not well.

श्री नरेश अग्रवाल : और जवाब भी वही दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(2 जी/एएससी पर जारी)

ASC-PB/2G/2.25

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : क्योंकि संतोष जी को तो हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मानकर चल रहे थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, he has informed me. …(Interruptions)… See, the Finance Minister has informed me … …(Interruptions)…

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, I am saying the same thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He will come and reply.

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, I am saying the same thing that he is ill. I pray to God that he comes soon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: And he will come for reply. The only thing is, not today.

श्री नरेश अग्रवाल : यहां संतोष जी बैठे हुए हैं। हम लोग तो कुछ और समझ रहे थे। अब तो हमें भी….(व्यवधान)….

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please.

श्री नरेश अग्रवाल : अब तो हमें विश्वास होने लगा है कि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो सही है, उसके कहने में कभी हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने दलीय सीमाओं से हटकर वहां पर भाग लिया, क्योंकि यह एक परम्परा है कि outgoing Chief Minister oath में जाता है, तो हम वहां गए। हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। यह तो छोटी मानसिकता ने पैदा कर दिया कि हम राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध मानने लगे हैं। श्रीमन्, विचारों का मतभेद होता था, कभी व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता था। यह नहीं देखा जाता था कि हम किस दल में हैं और आप किस दल में हैं। हम सब संसद सदस्य हैं और हम सब जन प्रतिनिधि हैं और हम सबका अधिकार बराबर है, यह ठीक है कि हमारे विचार अलग हैं। मैं इसीलिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जीत उनकी है, बीजेपी की नहीं है, वोट मोदी जी को दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को भी बधाई दूंगा और उनसे एक ही बात कहूंगा कि राजनीति में जब आदमी बढ़ता है, तो लोग दो चीजें देखते हैं कि राजनीतिक छवि कैसी है और प्रशासनिक छवि कैसी है। राजनीतिक छवि तो सबने देख ली है। अब उनसे उम्मीद है कि वे अपनी प्रशासनिक छवि दिखाएंगे। हम लोगों ने 6 महीने का समय दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उनको कोई ब्लैंक कागज दे दिया है। ....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. …(Interruptions)… Please. Please. …(Interruptions)… Nareshji, address the Chair and proceed. …(Interruptions)… Address the Chair and proceed. बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल : हमारी ये बहन यहां पहली बार आई हैं। अभी इनको भी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आज ही कुछ अनुभव मिल जाए। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि दो अनुभव होते हैं। एक प्रशासनिक अनुभव होता है और एक राजनीतिक अनुभव होता है। राजनीतिक अनुभव भी देखने को मिलेगा। हमने 6 महीने का समय दिया है। मीडिया के लोग आज भी हमसे पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कत्ल होने लगे हैं। मैंने कहा कि हमारी सरकार होती तो तब तो होता कि कानून-व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत वायदे किए हैं। आपने चुनाव के समय कहा था कि कैबिनेट पहली बैठक में किसान का कर्ज़ा माफ होगा और बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, तो कम से कम आप दिल्ली की सरकार से करा दीजिए। कांग्रेस के लोग तो कर्ज़ा माफी के लिए PM से मिलने गए थे। हम सब लोगों ने कहा था कि अगर इस देश के किसान का कर्ज़ा माफ नहीं हुआ, इस देश के किसान ने अगर तरक्की नहीं की, तो उचित नहीं होगा। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि बजट तैयार करते समय वित्त मंत्री देश के पूंजीपतियों को, देश के उद्योगपतियों को बुलाते हैं, लेकिन किसानों से कभी सलाह नहीं लेते हैं कि बजट किस प्रकार बनना चाहिए। इसीलिए GDP में एग्रीकल्चर का प्रतिशत निरंतर गिरता चला गया। यह प्रतिशत किसी जमाने में 42 प्रतिशत था। आज हम 19 per cent पर आ गए हैं। हमें यह सोचना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम नहीं

सोचेंगे और विचार नहीं करेंगे, तो हमारे सामने एक विशेष परिस्थिति खड़ी जो जाएगी। इन्होंने बहुत वायदे किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वे अपने वायदों को पूरा करें। मैं मानता हूं कि जब संसाधन कम होते हैं, तो बजट बनाकर सबको लाभान्वित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं मंत्री था, तो मैं भी देखता था कि हमारी GDP घट रही है। हमें यह भी देखना है कि हमने क्या वायदा किया था और कहां पर हम पहुंच गए हैं। हालत यह है कि चीन ने हमारी पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया है। किसान को MSP नहीं मिल रही है।

(1H/LP पर जारी)

LP-SKC/2.30/2H

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : आज हमारे सामने, विश्व में एक अजीब स्थिति खड़ी हो गई है। आज ऐसा लगता है कि विश्व का कोई देश हमारे साथ नहीं है। कश्मीर अपने आप में जल रहा है। हम यहाँ सिर्फ वायदा करते हैं कि जब देश का प्रश्न आएगा, तो हम सब देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आएगी, हम राजनीति करने में कहीं दूर खड़े नहीं होंगे। हम साधु नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं इन चार लाइनों के साथ बजट भाषण शुरू करूंगा :-

"हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता,
कहाँ तलक ये चिराग़ों को आजमाएगी।
कभी तो होगा उजालों का राज यहाँ,
कभी तो रात चिरागों से हार जाएगी।"

हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, कभी हार परमानेंट नहीं मानते, कभी जीत परमानेंट नहीं मानते। हमने बहुत लहरें देखी हैं। हमने 1971 की लहर देखी, 1977 की देखी, 1980 की देखी, 1984 की देखी, 1989 की लहर भी देखी। देश में बहुत लहरें आईं। यही बीजेपी, किसी एक लहर में पार्लियामेंट में, लोक सभा में केवल दो पर रह गई थी। ..(व्यवधान)..मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह जी को याद होगा। एक ज़माने में यही बीजेपी दो की संख्या पर रह गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। राजनीति को कभी भी परमानेंसी में नहीं लेना चाहिए, राजनीति temporary है। मैं तो कहता हूं कि राजनीति में "भूतपूर्व" शब्द ऐसा है, जो परमानेंट है, बाकी पद परमानेंट नहीं है। यदि हम यही सोचकर चलेंगे..(व्यवधान)..

श्री आनन्द शर्मा : यह एक ऐसा भूत है, जिसका कोई इलाज नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल : हाँ, इसका कोई इलाज नहीं।..(व्यवधान)..उपसभापति जी, तीन साल पहले, जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने promise किया था कि हम जीडीपी आठ परसेंट से ऊपर ले जाएंगे। यह घटती चली गई और आज सात परसेंट पर है। इनके आंकड़े खुद बताते हैं। जब नोटबंदी हुई थी, तो पूर्व प्रधान मंत्री और देश के बहुत बड़े economist आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था कि आप तैयार रहिए, हो सकता है कि दो परसेंट जीडीपी गिरे। जब उन्होंने यह बात कही थी, तब लोगों ने इसको हँसी में लिया था, लेकिन यह सत्यता कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। अगर जीडीपी निरंतर गिरती चली गई, तो हमारे सामने एक बड़ी भारी चुनौती खड़ी होगी। आज हम अपनी जीडीपी का 19 प्रतिशत विश्व को सिर्फ ब्याज देने में अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व से कर्ज़ ले रहे हैं। हम उनको जीडीपी का 19 प्रतिशत सिर्फ

ब्याज के तौर पर दे रहे हैं, बाकी और प्रशासनिक खर्चे, तमाम योजनाएँ आदि, यदि जीडीपी बहुत जादा गिरी तो देश में बेरोजगारी की क्या हालत होगी, क्या आपने कभी इस पर सोचा है? अगर जीडीपी कहीं छह परसेंट पर आ गई, तो हो सकता है कि हमारे नौजवान कहीं सड़कों पर न आ जाएँ।..(व्यवधान)..चलिए, आनन्द शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बार उठाया कि सब पर पे कमीशन लागू हो रहा है, सिर्फ एम.पीज. को पे कमीशन नहीं दे रहे। सबका पे कमीशन लागू हो गया, अब तो चपरासी की तनख्वाह भी हम लोगों से ज्यादा हो गई। श्री मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, आपका सौभाग्य है, आप तो नेता सदन हैं, हम आपको नेता सदन मान रहे हैं। ..(व्यवधान)..हैं ही नहीं, नेता सदन, तो आप ही हैं नेता सदन।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have promoted him!

SHRI NARESH AGRAWAL: Yes, Sir; I am promoting him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, the Chair also has to agree! …(Interruptions)…

श्री नरेश अग्रवाल : आप एग्री हैं, पूरा सदन एग्री कर रहा है।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, the entire House agrees.

श्री नरेश अग्रवाल : पूरा सदन एग्री कर रहा है। आज आप घोषणा कर दीजिए।..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair has not agreed! …(Interruptions)…

श्री नरेश अग्रवाल : आज आप घोषणा कर दीजिए।

श्री राम विचार नेताम : माननीय सदस्य, आपके नेतृत्व में आपका डेलिगेशन मिला था, उसके बारे में भी बता दीजिए कि वहाँ से क्या उत्तर मिला।

श्री नरेश अग्रवाल : सुन लीजिए साहब ।

श्री उपसभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल : मैं पी.एम. से मिलने गया था। मैंने पी.एम. से कहा, पी.एम ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के 12-14 एम.पीज. मिलने गए। हमारे बाद उनका नंबर था। वे लौटकर आए, तो मुँह लटकाया हुआ था, मालूम हुआ कि इतना डाँटा बीजेपी वालों को।..(व्यवधान)..12-14 एम.पीज. गए थे, कहा कि साहब, एम.पीज. की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मैं बैठा था, जब लौटकर आए, तो देखा, सब मुँह लटकाए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कि मैंने किस से पूछा, पर वे कहने लगे कि आज हम लोगों को बहुत डाँट पड़ी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : नरेश जी, यह हुआ कि आपने प्रोत्साहित किया था, लगता था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए उसमें यानी आपके प्रोत्साहन में लोग चले गए, लेकिन लौटकर आए तो उलटा हुआ।

(2J/KLG पर आगे)

KLG-HK/2J/2.35

श्री नरेश अग्रवाल: तो ऐसा हुआ। चूंकि आप पूछ रहे थे कि एम.पीज़ मिलने गए, तो क्या हुआ, तो हमने बताया कि यह हुआ।

प्रो. राम गोपाल यादव: अब तो उम्मीद इसलिए है कि जिन्होंने रिपोर्ट में रिकमंड किया था, वे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए। अब तो ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवाल: हां, यह भी बात ठीक है। योगी जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने रिकमंड किया था। वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हो गए हैं तो इस सम्मान में ही घोषणा हो जानी चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री हो गए हैं। श्रीमन्, अभी झटका लगा है, इसलिए हम लोगों को फ्लो में आने में समय लगेगा।

श्रीमन्, मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी एक परसेंट रह गई है, जो नए आंकड़े आए हैं उसमें हम एक परसेंट से भी नीचे चले गए हैं। देश में केवल 4 परसेंट लोग इन्कम टैक्स दे रहे हैं, बैंक का एनपीए बढ़ रहा है और हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए अपने बजट से हम बैंकों को दे रहे हैं। चिदम्बरम जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे भी कई बार कहा था कि हम अपना पैसा बैंकों को क्यों दें? आज बैंक के चेयरमैन की हालत यह है, आप एम.पी. की बात तो छोड़ दीजिए, मंत्री भी अगर चेयरमैन को फोन कर दें तो चेयरमैन कहता है कि अच्छा, मंत्री से फोन कराया है और फिर काम उल्टा कर देता है। आप कहें, तो मैं मिसाल दे दूं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तीन दिन पहले का किस्सा है, मैंने किससे फोन कराया और उसका क्या रिजल्ट आया? बैंक के सीएमडी पर नकेल कसनी होगी। अभी 7000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, ऐशो-आराम पर वे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बारे में कभी किसी ने सोचा है। सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो रहा है। आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जीडीपी और गिरेगी। मैं चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें, तो सही आंकड़ों के तथ्य पर बता दें

कि जीडीपी रियल कितना है? क्योंकि उनके आंकड़ों से तो न महंगाई है, न जीडीपी गिरा है, देश ठीक चल रहा है और हम विश्व में बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर सही आंकड़े बताए जाएं, तो मैं कहूंगा कि देश कम से कम इतना तो जान सकेगा कि देश के सामने क्या तकलीफ है?

श्रीमन्, हम सब लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया, लेकिन हम चाहते थे कि काला धन वापस आए। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वे जनता को समझाने में सफल हो गए, क्योंकि राजनीति में वही आदमी बढ़िया होता है, जो जनता को समझाने में सफल हो जाए। वे गरीब को बताने में सफल हो गए कि हमने नोटबंदी में अमीर को गरीब बना दिया। इस देश में सरकारें नारा देती हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इस सरकार ने नारा दिया कि हम अमीरी हटाएंगे। आप इसमें सफल हुए, अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ी। हम उनसे कहते रहे कि कोई उद्योगपति लाइन में नहीं लगा, लेकिन उनको लगा कि जन धन खाते में रुपया आ जाएगा। हम भी उन्हें साल, दो साल का समय दे रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव तक आ जाए, तो बहुत अच्छा है। हम सब यह जानना चाहते हैं कि नोटबंदी से पहले रिजर्व बैंक ने कितने हजार और पांच सौ के नोट जारी किए थे, क्योंकि आप कहते हैं कि 82 परसेंट, 88 परसेंट नोट आए, जो हजार और पांच सौ के नोट मार्केट में थे, उनकी फिगर 14 लाख 72 हजार करोड़ की आई थी। तो ये कितने जारी हुए थे और नोटबंदी के बाद कितने जमा हुए? मैं बिल्कुल साफ जानना चाहता हूँ कि कितने जारी हुए और कितने जमा हुए?

श्री आनन्द शर्मा: अभी तक गिनती चल रही है।

श्री नरेश अग्रवाल: क्या काले धन के रूप में कोई पैसा आया? हम लोगों ने विदेश से काला धन लाने की बात की थी, क्योंकि चुनाव में सवाल था कि विदेश से काला धन लाएंगे, मगर ये तो देश में काला धन खोजने लगे। पनामा से हजारों कंपनियों का आया कि पनामा के माध्यम से हजारों कंपनियां पनामा में बनीं और हिंदुस्तान का ब्लैक मनी पनामा में व्हाइट हुआ। हिंदुस्तान में एफडीआई के माध्यम से वहां चला गया। सरकार को एक-एक नाम मालूम है। पेपर्स में तमाम नाम आए। स्विट्जरलैंड के बैंकों में किस-किस का पैसा जमा है, तमाम नाम आए, लेकिन क्या वह बताया गया? देश में आखिर काला धन कितना है, पता तो लगे! अब आपने नए नोट कितने जारी किए? आपने कह दिया कि नए नोट पर हमारी दो रुपए छपाई आई, तीन रुपए छपाई आई, लेकिन आप कागज का मूल्य तो बता नहीं रहे कि नोट के कागज का मूल्य क्या है? खाली छपाई का नहीं, कागज का मूल्य भी आप बताइए। फिर यह दो हजार रुपए के नकली नोट अभी से बाजार में आ गए, तो आपने नए नोट छापने में कौन सी सेफ्टी रखी?

(2के/एकेजी-केएसके पर जारी)

AKG-KSK/2K/2.40

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : आप कहते हैं कि हमने इसमें higher security रखी है, तो फिर कहाँ से नकली नोट आ रहे हैं! मैं रोज पढ़ लेता हूँ कि आज वहाँ दो हजार रुपए के नकली नोट ...(व्यवधान)...

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान) : वे चूरन वाले नोट हैं।

श्री नरेश अग्रवाल : चलिए, चूरन वाले समझ कर मान लीजिए, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह आपका कहना है, यह मेरा कहना नहीं है। मैं यह बात पूछना चाहता हूँ कि हम जहाँ से नोट का कागज ले रहे हैं, अगर वहीं से पाकिस्तान और बंगलादेश भी कागज ले रहे हैं और डाई भी वहीं से ले रहे हैं, तो यह क्यों है? यह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बंगलादेश से नकली नोट हमारे पास आ रहा है। आप इस चीज पर कम से कम गौर तो करें। अगर आप यह भी बता दें कि अब तक कितना काला धन विदेश में है और वह कब तक वापस आएगा, तो शायद इस देश पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा।

हम सब किसान की बात करते हैं। अभी हमने कहा था कि किसान की कर्ज माफी की बड़ी इच्छा है। कांग्रेस ने एक बार उनका कर्ज माफ किया था। प्रधान मंत्री जी चुनाव में कहते रहे कि यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफ हो जाएगा। हम वह mechanism नहीं समझ पाए। हमारे मित्र बैठे हैं, वे मुजफ्फरनगर के सांसद हैं और मंत्री भी हैं, ये शायद हमें ज्यादा अच्छा mechanism समझा देंगे कि नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्ज राज्य सरकार कैसे माफ कर सकती है? यह कौन सा नया mechanism पैदा हो गया? अगर इसे एक राज्य सरकार माफ करेगी और उसका खर्च आप उठाएँगे, तो जो देश के अन्य राज्य हैं, वहाँ के किसानों का क्या होगा? उन राज्यों के सामने क्या समस्या पैदा होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CMD, अरुंधती भट्टाचार्य ने खुल कर विरोध किया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)... चलिए, आप घोषणा कर दीजिए। आप ही इसकी घोषणा कर दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने तो कह दिया कि हम 14 दिन में गन्ना किसानों का पैसा भी दे देंगे। स्टेट बैंक

ऑफ इंडिया की CMD ने खुल कर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे बैंकों का किसानों का कर्ज माफ करते रहे, तो भविष्य में किसान जो कर्ज लेंगे, वे कभी उसे अदा नहीं करेंगे और उससे बैंकों की स्थिति और खराब होगी। आज हम dilemma में हैं। किसी को पता ही नहीं है कि आप किसानों का कर्ज माफ करेंगे या नहीं। कल यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एक राज्य में तो किसानों का कर्ज माफ होगा, क्योंकि जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, तो हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया था। हमारा अधिकार था राज्य को-ऑपरेटिव बैंक का कर्ज माफ करने का, हमारा अधिकार था भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ करने का, हमने अपने उस अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन हम नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्ज तो माफ ही नहीं कर सकते थे। मैं चाहूँगा कि कर्ज माफी पर यह सरकार स्पष्ट उत्तर दे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गंगवार जी, आप वित्त मंत्री जी से कह दीजिएगा कि वे ही इसका उत्तर दे दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आपने कहा था कि आप किसान को उपज का डेढ़ गुणा मूल्य देंगे। नोटबंदी में धान की जो कीमत हुई, सबको मालूम है। आप किसान की सब्सिडी और कम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... अगर आप हर चीज को वोट में लेंगी, तो बहुत मुश्किल सामने आ जाएगी। हमको चुनाव जीतते हुए 40 साल हो गए, आप पहली बार जीती हैं, अभी आपको राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमको चुनाव जीतते हुए लगातार 40 साल हो गए। ...(व्यवधान)... अब भी जीत गए, इस लहर में भी जीते। जब आँधी थी, उस आँधी में भी जीते। ...(व्यवधान)... हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्या चीज है?

हमसे अच्छा कटाक्ष कोई नहीं करता है। आप महिला हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सीमाओं के अन्दर हूँ। ...(व्यवधान)...

डा. संजीव कुमार बालियान : मैंने पहले ही समझा दिया है।

श्री नरेश अग्रवाल : आपने अच्छा किया। गिरिराज भाई हमारे लिए ठीक हैं, क्योंकि ये भी free for all हैं और हम भी free for all हैं। हम और गिरिराज भाई, दोनों ठीक हैं। ...(व्यवधान)...

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : खून एक ही है।

श्री नरेश अग्रवाल : हम दोनों भाई हैं, खून तो एक ही होगा। लाल इनका भी है और लाल हमारा भी है, किसी का खून सफेद नहीं है।

(2एल/एससीएच पर जारी)

SCH-GSP/2.45/2L

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : महोदय, सब्सिडी निरंतर कम हो रही है। आप खाद पर सब्सिडी कम कर रहे हैं, बीज पर कम कर रहे हैं और पानी का दाम बढ़ रहा है। किसान के इस्तेमाल की हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, लेकिन किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा। किसान से खरीद का मार्केट में आपने कोई सिस्टम नहीं रखा है। एफसीआई की हालत यह है कि भ्रष्टाचार वहां चरम सीमा पर है। स्टोरेज आपके पास है नहीं, हर साल यह बात कही जाती है। हिन्दुस्तान में करीब 50,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न इसलिए सड़ता है कि हमारे पास उसको रखने की उचित व्यवस्था नहीं है,

कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण अनाज और खाने की दूसरी चीज़ें सड़ जाती हैं। आखिर इन परिस्थितियों में हम किसान को कैसे जिंदा रखेंगे?

किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि उसकी जोत छोटी होती चली जा रही है। आजादी के बाद चार-पांच पीढ़ियां खड़ी हो गईं, भूमि का बंटवारा होता चला गया और आज किसान दो एकड़, अढ़ाई एकड़ और तीन एकड़ का रह गया है। नौजवानों की रुचि खेती में कम हो गई है, वे नौकरियों की तरफ और व्यापार की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में आखिर किसान कैसे जिंदा रहेगा? उसकी भूमि उपजाऊ कैसे बनी रहेगी? देश के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या खाली यूपी के सामने नहीं है, यह समस्या पूरे देश के सामने है। भूमि का इतनी बार बंटवारा हो गया है और जोत इतनी छोटी हो गई है कि अगर हम एक ट्रेक्टर लें और उस ट्रेक्टर पर अगर सामान लोड करने का काम न करें, ढुलाई का काम न करें, तो हम ट्रेक्टर की किश्त बैंक को नहीं दे सकते। यह स्थिति पैदा हो गई है। इस तरह आखिर किसान का भला हम कैसे करेंगे? हम सब कहते हैं कि यह देश किसानों का है, हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, हम गांवों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि गांवों की आबादी शहरों की तरफ भाग रही है। पूरे विश्व में शहर का रहने वाला आदमी गांव की तरफ जा रहा है। लंदन, अमरीका इत्यादि देशों में कोई आदमी शहर में रहना नहीं चाहता, इसलिए वह गांव की तरफ जा रहा है। इन देशों में गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, लेकिन भारत में शहरों की आबादी इतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है कि आज कोई भी ऐसा शहर नहीं है, जो किलोमीटर्स में न बढ़ गया हो, चाहे वह छोटा

शहर हो या बड़ा शहर हो। हर आदमी यह सोचता है कि थोड़ा सा पैसा हो और हम शहर में रहने चलें, क्योंकि शहर में नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध होंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और बिजली भी मिलेगी। यह जो उल्टा चलन है, इस चलन को हमें रोकना पड़ेगा। किसानों की आत्महत्याओं को भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर हमने इस पर अभी भी रोक नहीं लगाई, तो हमारा दुर्भाग्य होगा।

हमारा एक कहना यह भी है कि किसान की उपज का मूल्य तय करने के लिए आईएएस लोगों की कमेटी बना दी जाती है। जब मूल्य तय होता है, तो वह कमेटी बड़ा अहसान करती है कि गेहूं का MSP 20 रुपये बढ़ा दिया गया, दाल का MSP 15 रुपये बढ़ा दिया गया।

श्रीमन्, अगर हम किसान को प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो वह उचित नहीं होगा। आज हमारे यहां दाल का कितना इम्पोर्ट है? बालियान जी, आप स्वयं किसान हैं। मैं जिन बातों को उठा रहा हूं, उनमें किसानों की असलियत को उठा रहा हूं। गेहूं की लागत कीमत 1950 रुपये है और उसका MSP 1650 रुपये है। जो लोग धान और गेहूं की बाली में फर्क न पहचानते हों, उन आईएएस लोगों को इसके बारे में क्या मालूम? ऐसे लोगों से आप कहें कि आप किसान की उपज की कीमत तय कर दीजिए, तो किसान को कहां से न्याय मिलेगा? एक बार शरद जी जब मंत्री थे, तब हमने उनसे एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने बताया था कि किसानों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी, उसमें टाटा और अम्बानी वगैरह सदस्य थे। प्रश्न के जवाब में यह लिखा था, वह जवाब

मैं रिकॉर्ड से निकाल सकता हूं। अगर टाटा, अम्बानी और गोदरेज जैसे बड़े लोग किसान को एडवाइस देंगे, तो किसान का भविष्य क्या होगा?

महोदय, मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि एमएसपी तय करने की कमेटी में कम से कम दो योग्य किसान, जिनको वे उचित समझें, जो सबसे प्रगतिशील किसान हों, उनको सदस्य बनाया जाए, जिससे वे किसानों का पक्ष भी रख सकें।

(2m-rpm पर जारी)

RPM-SK/2M/2.50

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : उपसभापति महोदय, देश में import हो रहा है। आज सारी दालें म्यांमार, कनाडा और अन्य देशों से आयात की जा रही हैं। जब श्री आनन्द शर्मा जी, वाणिज्य मंत्री थे, तब से ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, उसमें कितना बड़ा घालमेल है, यह सभी को पता है। एक दिन यह विषय श्री शरद यादव ने उठाया था। आज हम गेहूं और शूगर का इम्पोर्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा किया जाएगा, तो किसानों को कहां से और कैसे उनकी उपज का मूल्य मिलेगा? अगर शूगर मिल और किसान, दोनों ही जिन्दा नहीं रहेंगे, तो भी ठीक नहीं होगा। हम दाल की MSP रु. 3,000/- रख रहे हैं और बाहर से दाल रु. 4,000/- प्रति क्विंटल आ रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम किसान को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं? क्या हमारे देश का किसान कमजोर है या हमारे देश का किसान अनभिज्ञ है? वह खुद ही इतना अनाज पैदा कर देगा जिससे आयात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज वह जमाना गया जब अमेरिका से लाल गेहूं हिन्दुस्तान आता था।

श्री राजीव शुक्ल: माननीय उपसभापति जी, आज विदेशों से गेहूं आयात किया जा रहा है। आज zero per cent import duty कर दी गई है। हमें बताया गया है कि देश में गेहूं का उत्पादन लगभग नौ लाख टन होने की संभावना है। यदि ऐसा है और विदेश से गेहूं आयात किया जाएगा, तो देश के किसान तो मारे जाएंगे।

श्री आनन्द शर्मा: ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी गई है।

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्होंने खाद्य पदार्थों पर जो import duty खत्म की है या उसे ज़ीरो परसेंट कर दिया गया है, उसे इतना बढ़ा दिया जाए जिससे खाद्य पदार्थों का आयात रुक जाए। यदि ऐसा होगा, तो देश का किसान अपने देश में ही बहुत खाद्यान्न पैदा करेगा, जिससे देश की जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे उसकी उपज का डेढ़ गुना दाम मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा, तो मैं सबसे अच्छा समझूंगा।

महोदय, हम सब गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद हम अभी तक गरीबी की परिभाषा तय नहीं कर पाए हैं। प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग बन गया है, उसने तय किया था कि गांव में रु. 18.00 प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं रहेगा और शहर में जो रु. 23.00 कमाता है, वह गरीब नहीं रहेगा। हम सब ने इसे चैलेंज किया था। हम सब ने इसका विरोध किया था। हमारा कहना था कि 18 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलती है। अब 10 रुपए प्रति कुल्हड़ के हिसाब से स्टेशन पर चाय मिलने लगी है। रु. 18.00 प्रति दिन में आप कैसे गुजारा करेंगे? अब तक गरीबी की परिभाषा तय करने के लिए चार कमीशन बैठ चुके हैं। एन.सी. सक्सेना कमीशन, अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन, तेंदुलकर कमीशन और रंगराजन कमीशन। हर कमीशन ने अपनी

रिपोर्ट दी है। अब शायद आपने कोई पांचवां कमीशन भी बैठा दिया है, लेकिन आप कब तक कमीशन बैठाएंगे? आखिर आप कब तक बीपीएल की परिभाषा करेंगे और देश में गरीबी रेखा आप कहां पर मानेंगे? मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ आंकड़ों में गरीबी खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि आंकड़ों में गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन वस्तुत: तो गरीबी खत्म नहीं होगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस देश में 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब हों, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you need a Commission to decide what poverty is?

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति जी, मैं कमीशन नहीं चाहता हूं। कमीशन बनाना, तो समस्या को टालने वाली बात है। मेरा कहना है कि सरकार अपनी विल पॉवर से घोषणा करे। देश से गरीबी कैसे खत्म होगी, आखिर गरीबी की कोई सीमा रेखा तो तय करे। हम टालते जाते हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं, तो तमाम भाषण देते हैं।

महोदय, आज मैं व्हाट्सऐप पर एक मैसेज देख रहा था, जिसमें आसाराम बापू जी से सभी बड़े-बड़े नेता आशीर्वाद ले रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा कि उसमें कौन-कौन थे। आज ही मैं देख रहा था कि आसाराम बापू के सामने हमारे वे लोग, जिन्हें हम देश का कर्णधार मानते हैं और जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वे सभी बापू जी के सामने झुके हुए थे और बापू जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और बापू जी अब जेल में हैं। किस इल्जाम में पड़े हैं, यह सब जानते हैं।

महोदय, हमें गरीबी की कहीं न कहीं एक सीमा तय करनी चाहिए और हमें गरीबी को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए भले ही हमें बीपीएल की संख्या बढ़ानी

पड़े, लेकिन एक संकल्प होना चाहिए कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, देश में कोई नंगा नहीं रहेगा, देश में कोई बिना मकान के नहीं रहेगा और देश में एजुकेशन बढ़ेगी। अगर हम देश की इतने सालों की आजादी के बाद यह भी नहीं कर सके, तो आजादी का क्या फायदा? देश में इतना बजट खर्च हो रहा है, आखिर यह कहां जा रहा है? इन चीजों को देखिए। देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इस बात के हम भी पक्ष में हैं। देश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, उसकी कोई रूप-रेखा बनेगी, कोई मानक तय होंगे, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।

महोदय, आज देश में बेरोजगारी की क्या हालत है, इसे सब जानते हैं। आज विश्व में हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की टोटल आबादी के 60 प्रतिशत से ज्यादा हमारे देश में नौजवान हैं। चीन ने भी जब एक से ज्यादा बच्चे करने पर रोक लगाई, तो उसके सामने भी नौजवान आबादी का प्रश्न पैदा हो गया और उसने भी एक बच्चे की बजाय दो बच्चे पैदा करने का सिद्धान्त अपनाया। जापान में 80 प्रतिशत आबादी बुड्ढों की हो गई। जापान के पास सवाल है कि ओल्ड एज होम कहां बनें?

(2एन/पीएसवी पर जारी)

PSV-YSR/2N/2.55

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत): जापान को ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ओल्ड एज होम्स बनाने पड़े। हम सौभाग्यशाली हैं कि 60 परसेंट नौजवान हैं। तो आपने जो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, तब तो अब तक 6 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। आपने पैरा मिलिट्री में नौकरी बंद कर दी, बैंकों में नौकरी बंद कर दी, सिविल एविएशन में सारी नौकरियाँ बंद कर दीं। तो आप अगर नौकरी बंद करते गए,

तो कहीं ऐसा न हो कि देश के प्रतिभाशाली लोग, जो देश से पलायन कर रहे हैं, वह पलायन और न बढ़ जाए। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। ...(व्यवधान)... इस सरकार ने यह अच्छा किया कि बुजुर्गों का एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया, तय कर दिया कि इस उम्र वाले जितने बुजुर्ग होंगे, वे मार्गदर्शक मंडल में होंगे। यह एक नया रास्ता दे दिया। तो कम से कम हमारे देश में ओल्ड एज होम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ...(व्यवधान)... अब आपसे शिक्षा ली, तो कहीं न कहीं हम भी उसको लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे? कहीं न कहीं कोई तो गाइडलाइन हमें माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी?

श्रीमन्, अभी तो मेरा बहुत समय बचा है। अभी तो आधा ही टाइम हुआ है। शिक्षा- हम सब मानते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। मुझे याद है कि कांग्रेस एक बार सत्र में एक विधेयक लाई थी। डा. मनमोहन सिंह जी के जमाने में आया था- 'राइट टू एजुकेशन', 'एजुकेशन टू ऑल'। उसके लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' चला, 'प्रौढ़ शिक्षा अभियान' चला, 'अनौपचारिक शिक्षा' चली। यह दुर्भाग्य है कि देश में इतने प्रकार की शिक्षा हो गई कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी शिक्षा कहाँ होगी। कहीं उर्दू शिक्षा, कहीं संस्कृत शिक्षा तो कहीं कॉन्वेंट शिक्षा, देश में इतने प्रकार की शिक्षा हो गई कि कौन सी शिक्षा का आदमी शिक्षित माना जाए, यह बात हम समझ नहीं पाए। राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा गया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा कि 65 परसेंट आप खर्च कीजिए, 35 परसेंट केन्द्र सरकार उस पर खर्च करेगी। राज्य सरकारों ने उस पर आपत्ति की और राज्य सरकारों ने कहा कि 65 परसेंट आप खर्च कीजिए और 35 परसेंट हम करेंगे और 'एजुकेशन टू ऑल' हम करेंगे। वह प्रस्ताव रुक

गया। वह आज पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप उस पर कोई निर्णय लीजिए। आज केरल में 100 परसेंट एजुकेशन है, तो देश का सबसे विकसित प्रांत अगर कोई है, तो केरल है। आज साउथ में एजुकेशन का प्रतिशत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट साउथ में है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी अगर कहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में है, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान आदि में। पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उन्हीं राज्यों में ज्यादा है, जिन राज्यों में एजुकेशन कम है। हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, 2050 में आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश हम बन जाएँगे। कहाँ से इन्फ्रास्ट्रक्चर लाएँगे? आज वैसे भी हालत यह है कि ट्रेनों में जगह नहीं, बसों में जगह नहीं, प्लेन्स में जगह नहीं, सड़कों पर रोज जाम लग रहे हैं। आज चलना मुश्किल हो गया है। कहाँ कौन जाम में पड़ जाए, कहना मुश्किल है। एक दिन तो गडकरी जी डेढ़ घंटे जाम में फँस गए। वे एक शादी अटेंड करके गुरुग्राम से लौट रहे थे। तो अगर हमने एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं किया-- मैं तो प्राइवेट सेक्टर को बधाई दूँगा कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन सिस्टम को-- यह ठीक है कि उन्होंने उसको कमाई का धंधा भी बनाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कम से कम देश में एजुकेशन तो दी। आज हमारे देश की कोई भी युनिवर्सिटी विश्व के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। आज जब विश्व के 100 युनिवर्सिटीज़ के नाम आते हैं, तो हिन्दुस्तान की कोई युनिवर्सिटी उसमें नहीं आती है। आखिर इसका क्या कारण है? हमने यूजीसी पर कभी कमांड की? क्यों हम यूजीसी पर कमांड नहीं करते हैं, जबकि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन का यह काम है कि वह युनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड मेनटेन करे? 60 परसेंट युनिवर्सिटीज़ में टीचर्स नहीं हैं, इंटर कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं,

डिग्री कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की हालत बहुत खस्ता है। वहाँ टीचर्स नहीं हैं। हम जब टीचर्स नहीं रखेंगे, एजुकेशन की बात क्या करेंगे? आज एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में भी यही हालत है। हमारे यहाँ एक आठवीं पास लड़का आया। उसने बोर्ड से फर्स्ट क्लास पास किया था, 90 परसेंट नम्बर थे। उसने बोला कि नौवीं में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया और कहा कि यह फर्स्ट क्लास पास लड़का है, आप नौवीं में इसका एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तब उसने मुझे उसके टेस्ट की जब कॉपी दिखाई, तो चारों सब्जेक्ट्स में ज़ीरो नम्बर पाया। तो अगर नकल से हमें कोई डिग्री मिलेगी, अगर नकल ही एजुकेशन का माध्यम होगा-- सिर्फ डिग्री?

(2ओ/वीएनके पर जारी)